



अंबानी के “वनतारा” की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित की

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चेलमेश्वर के नेतृत्व वाली एसआईटी को 12 सितम्बर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 26 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात स्थित अनंत अंबानी द्वारा स्थापित ‘वनतारा’ रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया है। अदालत ने कहा कि सामान्यतः ऐसे आरोपों पर आधारित याचिका, जिनके समर्थन में कोई ठोस सबूत न हो, कानून की दृष्टि में विचारणीय नहीं होती और प्राथमिक स्तर पर ही खारिज की जानी चाहिए।

इसके बावजूद, कोर्ट ने मामले की तथ्यात्मक जांच पड़ताल के लिए जांच आवश्यक मानी है और एसआईटी को 12 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। एसआईटी का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस जस्ती चेलमेश्वर करेंगे और आयोग के अन्य

■ सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एडवोकेट जया सुकीन व देव शर्मा की याचिका पर दिए जिनमें अखबारों में छपी खबरों के आधार पर पशु अधिकारों के हनन व पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।

■ कोर्ट ने एसआईटी गठित करते समय हालांकि यह भी कहा, कि जिन आरोपों की पुष्टि के लिए ठोस सबूत न हों वे याचिकाएं खारिज कर दी जानी चाहिए पर इस मामले से तथ्यात्मक जांच जरूरी है।

■ वनतारा असल में वन्यजीवों का पुनर्वास केंद्र है जहां देश विदेश से जंगली जानवर लाए जाते हैं। इस केंद्र की स्थापना अनन्त अंबानी ने की है।

सदस्य होंगे, बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, राघवेंद्र चौहान, मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त हेमंत नगराले तथा अतिरिक्त आयुक्त, कस्टम्स अनीश गुप्ता। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पंकज मिथल और पीबी वराले की बैंच ने यह

आदेश एडवोकेट सी.आर. जया सुकीन और देव शर्मा द्वारा दायर दो याचिकाओं के आधार पर पारित किया है। इन याचिकाओं में मांग की गई थी कि वनतारा रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की कार्यप्रणाली की स्वतंत्र जांच कराई जाए।

याचिकाओं में लगाए गए आरोप अखबारों में छपी रिपोर्टों पर आधारित हैं और उनके समर्थन में कोई ठोस सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए। फिर भी, अदालत ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करने की बजाय, एक तथ्यान्वेषण जांच का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने से जिन मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी है, उनमें शामिल हैं: वनतारा द्वारा भारत और विदेशों से जानवरों, विशेष रूप से हाथियों का अधिग्रहण किन परिस्थितियों में और किस प्रक्रिया से किया गया।

क्या ये गतिविधियाँ वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, तथा चिड़ियाघर नियमों के अनुरूप हैं? क्या जानवरों या उनके उत्पादों के व्यापार संबंधी नियमों का पालन किया गया है? क्या वहां पशुपालन, पशु चिकित्सा देखभाल और पशु कल्याण से संबंधित मानकों का पालन हो रहा है?

वैष्णो देवी मार्ग पर भूस्खलन में 6 की मौत

जम्मू, 26 अगस्त। जम्मू के पास कटरा स्थित श्री माता वैष्णो देवी मार्ग में अर्धकुवारी के पास मंगलवार को भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गयी और 14 अन्य घायल हो गये हैं। श्री माता वैष्णो देवी श्रावन बोर्ड ने यह जानकारी दी।

श्राइन बोर्ड ने कहा कि अर्धकुवारी के पास हुए इस भूस्खलन में घायल हुए लोगों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। दूसरी ओर जम्मू के सभी स्कूल बुधवार को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। श्राइन बोर्ड और सुरक्षा बलों ने राहत और

■ श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी तौर पर रोक दी गई।

बचाव कार्य शुरू कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर माता वैष्णो देवी की यात्रा को अस्थायी तौर पर रोक दिया गया है। अर्धकुवारी से भवन तक का मार्ग बंद कर दिया गया है। निचले ट्रंक से भी श्रद्धालुओं की आवाजाही सीमित कर दी गई है। जम्मू प्रशासन ने खराब मौसम और क्षेत्र भर में अलग अलग स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होने के मद्देनजर सभी सरकारी और निजी स्कूल कल बंद रखने का निर्देश दिया है।

कौन पैदा करवा रहा है “ट्राइबल लीडर” बिरसा मुंडा और अम्बेडकर के बीच टकराव की स्थिति?

कोटा में भारतीय रेल्वे एस.सी./एस.टी. एसोसिएशन को आवंटित आवास में अम्बेडकर की मूर्ति के समक्ष अनाधिकृत तरीके से क्वाों लगाई गई बिरसा मुंडा की मूर्ति?

- इस मामले में हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में कहा गया कि एसोसिएशन के अधिकारी “ट्राइबल” महानायक बिरसा मुंडा द्वारा, अनुसूचित जनजाति के हकों के लिए किए गए संघर्ष का भरपूर सम्मान करते हैं, परन्तु जिस जोर-जबरदस्ती और अनाधिकृत तरीके से उनकी मूर्ति स्थापित की गई, उससे केवल अनुसूचित जाति की भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि 2022 में एसोसिएशन का चुनाव हार चुके एक गुट ने लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिड़ला, के ओ.एस.डी. के साथ मिलकर अनाधिकृत तरीके से मूर्ति लगाने का कृत्य किया।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि एफ.आई.आर. भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन, राजनैतिक दबाव के चलते एफ.आर. लगाकर मामले को ठण्डे बस्ते में डाल दिया गया।

ईकाई ने हाईकोर्ट में रिट याचिका इसलिए दायर की थी क्योंकि पिछले वर्ष लोकसभा अध्यक्ष, ओम बिड़ला, के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (ओ.एस.डी.) ने एसोसिएशन को आवंटित

भवन में जबरदस्ती घूसकर, डॉ. भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति के सामने ही अनाधिकृत, अवैध तरीके से झारखण्ड प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के महानायक, बिरसा मुंडा, की मूर्ति का

लोकार्पण किया, और अनुसूचित जाति के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। याचिकाकर्ता के वकील सतीश पचौरी का कहना है कि वे बिरसा मुंडा के अनुसूचित

विधानसभा सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 28 को

जयपुर, 26 अगस्त। सोलहवीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र की बैठकें 1 सितम्बर से आरंभ होंगी। इससे पहले विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने, 28 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे विधान सभा में अपने कक्ष में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक रफीक खान, बसपा के

■ विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने यह परम्परा शुरू की थी।

मनोज कुमार, भारत आदिवासी पार्टी के थावर चन्द और रालोद के डॉ. सुभाष गर्ग को आमंत्रित किया गया है।

देवनानी ने विधान सभा अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद लोकसभा की तर्ज पर विधान सभा में भी सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने का निर्णय लिया था। राजस्थान विधान सभा में पहली बार सोलहवीं विधान सभा से आरंभ हुई यह सर्वदलीय बैठक चौथी बार हो रही है।

एससीओ समिट में मोदी और पुतिन का स्वागत खुद करेंगे जिनपिंग

शी इस कदम से ट्रंप को कड़ा मैसेज देना चाहते हैं कि टैरिफ वॉर में “ग्लोबल साउथ” एकजुट है

- चीन में हो रहे तियानजिन समिट में शामिल होने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन जा रहे हैं। 7 सालों में उनकी यह पहली चीन यात्रा है और भारत और चीन के बीच गंभीर सीमा विवाद को देखते हुए भी यह यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
- चीन भी चाहता है कि भारत अमेरिका के पाले में ना जाए क्योंकि एक स्वतंत्र तटस्थ भारत का चीन के साथ आना उसके लिए भी फायदेमंद हो सकता है।

आमंत्रित किया गया है। यह शिखर सम्मेलन भारत और चीन के बीच 2020 की यातक सीमा झड़पों के बाद तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है, क्योंकि अब भारत पर भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

पिछले साल कज़ान, रूस में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी मोदी, शी और पुतिन ने मंच साझा किया था, जबकि उस समय पश्चिमी नेताओं ने यूक्रेन युद्ध के चलते पुतिन से दूरी बना रखी थी। नई दिल्ली में रूसी दूतावास के अधिकारियों ने हाल ही में कहा कि मास्को को शी जिनपिंग और मोदी के साथ त्रिपक्षीय वार्ता की उम्मीद है।

चीनी राष्ट्रपति इस शिखर सम्मेलन

को एक ऐसे मंच के रूप में पेश करना चाहेंगे जो दिखाए कि अमेरिका के नेतृत्व से रहित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था कैसी हो सकती है और यह भी जनवरी तक वाइट हाउस ने चीन, ईरान, रूस और अब भारत पर भी जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। चाइना-ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट के संपादक एरिक ओलेंडर ने कहा, जरा देखिए ब्रिक्स ने डॉनल्ड ट्रंप को कितना विचलित किया है – यही तो इन मंचों की मूल भूमिका है। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन एससीओ के 2001 में गठन के बाद से अब तक का सबसे बड़ा सम्मेलन होगा। चीनी विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी ने इसे “अंतरराष्ट्रीय संबंधों की नई

प्रकार की संरचना में एक महत्वपूर्ण शक्ति” बताया।

हाल के वर्षों में भारत की नीति अमेरिका और इज़रायल के प्रति झुकाव के कारण एससीओ और ब्रिक्स के प्रति थोड़ी ठंडी पड़ी थी। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप के घमकाने की नीति भारत तथा प्रधानमंत्री मोदी के प्रति असम्मानजनक रवैये ने भारत को इन मंचों की ओर फिर से आकर्षित किया है।

सुरक्षाकारणों से गठित एससीओ, जो कभी छह यूरोशियाई देशों का समूह था, अब 10 स्थायी सदस्य और 16 संवाद व पर्यवेक्षक देशों तक फैल चुका है। इसका ध्यान अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक और सैन्य सहयोग तक भी विस्तारित हो चुका है।

हालाँकि विश्लेषकों का मानना है कि एससीओ ने अब तक ठोस सहयोग के नतीजे नहीं दिए हैं, लेकिन चीन के लिए यह अमेरिका के विरुद्ध ग्लोबल साउथ की एकजुटता दिखाने का महत्वपूर्ण मंच बन चुका है। कुछ विशेषज्ञ जो चीन को संदेह की दृष्टि से देखते हैं और अमेरिका भारत संबंध के समर्थक है उनका कहना है कि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका ने 50% टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी किया

नई दिल्ली, 26 अगस्त। अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले सामान पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने की योजना को एलान कर दिया है। यह वही टैरिफ है जिसकी घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पहले कर चुके हैं।

अमेरिकी होमलैंड सिक्यूरिटी विभाग ने एक ड्राफ्ट नोटिस जारी कर इसकी रूपरेखा पेश की। यह कदम ऐसे

■ नोटिस के अनुसार 27 अगस्त को रात 12.01 के बाद भारत के गोदामों से निकले माल पर यह टैरिफ लगेगा।

समय में उठाया जा रहा है, जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की कोशिशें ठप पड़ती नजर आ रही हैं। नोटिस में साफ कहा गया है कि यह बढ़ा हुआ टैरिफ भारत के उन उत्पादों पर लागू होगा, जो 27 अगस्त, 2025 को सुबह 12:01 बजे (पूर्वी डेलाइट समय) के बाद खपत के लिए आयात (शेष अंतिम पृष्ठ पर)